B-IV
L-42
MIH

वेवेल प्रस्ताव / शिमला सम्मेलन - जून 1945

• वायसराय वेवेल ने राजनीतिक पुनर्गठन के सन्दर्भ में एक प्रस्ताव रखा और उस पर भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया।

प्रस्ताव :-

• वायसराय परिषद में वायसराय एवं मुख्य सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे।

• इसमें हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी

• यह 1935 के अधिनियम के द्वारा संचालित होगा।

• जिन्ना की यह माँग थी कि मुसलमानों को केवल मुस्लिम लीग मनोनीत करेगी कांग्रेस ने इसका विरोध किया कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व मौलाना आजाद कर रहे थे। (सीमांत गांधी भी सम्मेलन में शामिल थे।

• वेवेल ने असहमति को देखते हुए बैठक को भंग कर दिया।

प्रत्यक्ष टकराव की तीन घटनाएं :-

• नवम्बर 1945 में आजाद हिन्द फौज के तीन अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा।
शहनवाज, ढिल्लो, पी के सहगल

- फरवरी 1946 आजाद हिन्द फौज के राशिद अली को सजा दी गई।

- 18 फरवरी 1946 नौ सेना का विद्रोह इसकी शुरुआत बाम्बे से हुई।

महत्व :-

- तीनों घटनाओं ने इस तथ्य को मजबूती से स्थापित किया कि सेना में राष्ट्रीय चेतना का व्यापक प्रसार हो चुका है और भारतीय सेना के भरोसे शासन करना मुश्किल है।

- इन सैनिकों के समर्थन में सेना और प्रशासन के अलग-अलग अंगो ने भी संवेदना दिखाई। यह भी अंग्रेजों की दृष्टिकोण से एक खतरनाक स्थिति थी। इनमें भी नौ सेना विद्रोह अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक चिंता की बात थी क्योंकि नौ सेना अंग्रेजों का सबसे मजबूत स्तम्भ था।

- नौ सैनिक विद्रोह के पश्चात ही सत्ता हस्तांतरण एवं संविधान सभा के निर्माण के सन्दर्भ में कैबिनेट मिशन को भेजा गया।

- प्रत्यक्ष टकराव की तीनो घटनाओं के समर्थन में अखिल भारतीय स्तर पर उग्र प्रतिरोध किया गया और इसमें आम लोगों की अधिक भागीदारी थी

- विरोध का आह्वान किसी राजनीतिक दल या नेता के द्वारा नहीं किया गया था।

KGS IAS

• विरोध के दौरान साम्प्रदायिक एकता बनी रही अंग्रेजों के लिए यह भी चिंता की बात थी

• विरोध को सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मिला।

कैबिनेट मिशन मार्च 1946

सदस्य → पैथिक लारेंस (भारत सचिव)
→ एलेक्जेंडर
→ क्रिप्स

यह तीनो लोग कैबिनेट रैंक के मंत्री थे।

उद्देश्य :-

संविधान सभा की संरचना और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के सन्दर्भ में प्रस्ताव देना।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

प्रस्ताव :-

• जबतक नयी सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक के लिए अन्तरिम सरकार की योजना।
• पाकिस्तान की माँग को अस्वीकृत किया हालांकि इसने अपेक्षाकृत एक कमजोर केन्द्रीय या संघीय सरकार का सुझाव दिया (केन्द्र सरकार के पास रक्षा, विदेश एवं संचार जैसे विषय होंगे।)
• अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतो के पास होंगी।

• 389 सदस्यीय संविधान सभा होगी। (लगभग दस लाख की आबादी पर एक सदस्य)

• इसमें ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य होंगे जिनको प्रांतीय विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा (अप्रत्यक्ष तौर पर)

• देशी रियासतों से 93 सदस्य होंगे और इन्हें मनोनीत किया जाएगा।

• संविधान का निर्माण तीन स्तरों पर होगी -

(केन्द्रीय, प्रांतीय एवं प्रांतो के वर्ग के लिए)

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

नोट :- छः हिन्दू बाहुल्य प्रांत, उत्तर पश्चिम में तीन मुस्लिम बाहुल्य प्रांत और उत्तर पूर्व में दो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत।

प्रतिक्रिया :- जिन्ना एवं कांग्रेस दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया लेकिन शीघ्र ही जिन्ना ने निम्नलिखित कारणों से इसका विरोध किया।

• जिन्ना प्रांतीय वर्गीकरण को अनिवार्य मान रहे थे वही कांग्रेस वैकल्पिक मान रही थी।

• अन्तरिम सरकार में मुसलमानों को केवल मुस्लिम लीग मनोनीत करेगी यह मांग भी

नहीं मानी गई।

- संविधान सभा में कांग्रेस की मजबूत स्थिति को देखते हुए।

नोट :-

- 1945 में केन्द्रीय एवं प्रांतीय चुनाव में आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग की स्थिति बेहतर थी।
- 1945 में ही ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ था और लेबर पार्टी की सरकार बनी थी।
- संविधान सभा एवं मिशन के प्रस्तावों का जिन्ना ने बहिष्कार किया और 16 अगस्त 1946 को जिन्ना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की और साम्प्रदायिक दंगों को भड़काया।
- सितम्बर 1946 नेहरू जी के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार का गठन।
- अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार में शामिल, साम्प्रदायिक दंगे जारी थे और लीग के मंत्री सरकार के संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

• फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। (दंगो की तीव्रता और बढ़ी)

• मार्च 1947 माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया।

• विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद भारत के स्वतंत्रता एवं विभाजन के सन्दर्भ में माउंटबेटन प्लान या 3 जून की योजना को जारी किया।(इसके निर्माण में पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी।)

• इसी योजना को 18 जुलाई 1947 को इण्डिया इंडिपेंडेंस अधिनियम के रूप में ब्रिटिश संसद से पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

ब्रिटिश काल में सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास

क्या है! धर्म का राजनीतिक फायदे के लिए दुरूपयोग, साम्प्रदायिक एक भ्रामक चेतना है जो इस भ्रामक विश्वास पर आधारित है कि एक धर्म मानने वालों का हित एक जैसा होता है

सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास :

भारत की परिस्थितियाँ :-

- भारत बहुधार्मिक देश है और ब्रिटिश काल में जो सीमित विकास हुआ उसका अधिकांशत लाभ मध्य वर्ग (विशेषकर हिन्दुओं को) को मिला जब इस वर्ग के द्वारा अधिकारों की मांग की जाने लगी तब अंग्रेजों ने बाँटो एवं राज करो की नीति पर मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावना को उभारा।
- सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन से भी साम्प्रदायिक चेतना को मजबूती मिली
- साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में भी सांप्रदायिक चेतना को मजबूत करने का काम किया जैसे- इतिहास मे प्राचीन काल को हिन्दू काल

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

और मध्य काल को मुस्लिम काल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

- गरमदलीय नेताओं ने आन्दोलन के दौरान जन समर्थन के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग और ब्रिटिश सरकार एवं रूढ़िवादी मुसलमानों ने कांग्रेस को हिन्दू संगठन के रूप में देखना प्रारम्भ किया। और इसके विरुद्ध संगठित होने की बात की जाने लगी।

- स्वदेशी आन्दोलन के दौरान मुस्लिम लीग का गठन जिसने सांप्रदायिक राजनीति को एक नयी पहचान दी और निरंतरता भी प्रदान की। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू महासभा का गठन हुआ।

- 1909 के अधिनियम में सरकार ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को वैधता प्रदान की और 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने भी।

- खिलाफत आन्दोलन के कारण राजनीति में रूढ़िवादी मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी।

- 1920-30 के दशक में सरकार ने मुस्लिम लीग के लगभग सभी मांगो को स्वीकार कर लिया फिर भी 1937 के चुनाव मे न तो लीग के पास जनाधार था नही हिन्दू महासभा के पास।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

• 1937 के पश्चात विभिन्न कारणों से लीग का जनाधार बढ़ा जैसे- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान प्रांतीय सरकारों में इन्हे शामिल किया गया तथा अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन में भी अलगाववादी स्वर को महत्व दिया गया।

• 1945 तक यह स्पष्ट था कि लीग के पास एक जनाधार है।

• 1945-47 के मध्य पाकिस्तान की लड़ाई सड़को पर, आम लोगों के स्तर पर एवं अन्तरिम सरकार के स्तर पर लड़ी गई ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक दंगो को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नही उठाया और अन्तरिम सरकार असहाय महसूस कर रही थी।

• इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष दो ही विकल्प थे प्रथम, साम्प्रदायिकता के विरूद्ध संघर्ष को जारी रखना और विभाजन का विरोध करना इसमे बड़ी संख्या में आम लोगों के मारे जाने का डर था तथा भारत में और भी अलगाववादी स्वर के उभरने का भी। द्वितीय विभाजन को स्वीकार कर परिस्थितियों पर यथाशीघ्र नियंत्रण स्थापित करना।

• दूसरा विकल्प दुखद अवश्य था लेकिन राष्ट्र हित मे इसी विकल्प को अपनाया गया।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

राजगोपालाचारी सूत्र - 1944

- सरकार चलाने में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक दूसरे का सहयोग करे और आजादी मिलने के पश्चात जिन क्षेत्रों को लेकर पाकिस्तान की माँग की जाती है वहाँ जनमत संग्रह कराया जायेगा और जनता यदि पक्ष में होगी तो इन प्रांतों को स्वायतता दी जाएगी।
- प्लान बाल्कन माउंटबेटन ने भारत को कई भागों मे विभाजित करने का प्लान बताया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

1924 में - बेलगाँव में अधिवेशन - गांधी जी (अध्यक्ष)

1925 में अधिवेशन - अध्यक्ष - सरोजनी नायडू।

1946 में मेरठ अधिवेशन - जे.बी. कृपलानी।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Learning Platform KHAN SIR